जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 268 प्रभात जालोर, गुरुवार 2 जनवरी, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

केजरीवाल ने संघ प्रमुख भागवत को ख़त लिखा

पत्र लिखने का मकसद फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व आर.एस.एस. व भाजपा के बीच मतभेद की खाई और गहरी करना

-श्री नन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जनवरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तथा आप के संस्थापक अरविन्द केजरीवाल ने भाजपा के गलत कार्यों के खिलाफ मोहन भागवत को एक शिकायती पत्र लिखकर भाजपा और आर.एस.एस. के बीच एक बार फिर दरार पैदा करने की कोशिश की है।

दिल्ली विधान सभा चुनावों से पहले, केजरीवाल ने भाजपा पर हमले तेज कर दिये हैं क्योंकि भाजपा फरवरी में होने वाले दिल्ली के चुनावों में दिल्ली की सत्ता छीनने की जबरदस्त तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने ऐसी रणनीति गत माह उस समय अपनाई थी, जब उन्होंने तेलुगूदेशम पार्टी के प्रमुख एन. चन्द्र बाबू नायडू तथा जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार को पत्र लिखे थे तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे बाबासाहेब अम्बेडकर के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह की "अपमानजनक टिप्पणी को लेकर स्वयं को भाजपा से अलग कर लें।" केजरीवाल ने आज आर.एस.एस. प्रमुख को पत्र भेजा है तथा उनसे पूछा है कि क्या वे भाजपा के अनुचित दाँव-पेचों का समर्थन करते हैं, जो भाजपा दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये अपना रही है। केजरीवाल ने शिकायत की है कि "भाजपा वोट खरीदने के लिये खुले आम पैसे बाँट रही है तथा मतदाता सूचियों से दलित और पूर्वांचल के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर हटाने में लगी हुई है। जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, उसने आप और केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वे दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या तथा बाँग्लादेशियों की दस्तावेजों और पैसों से मदद कर रहे हैं ताकि आगामी चुनावों में उनका उपयोग अपने वोट बैंक के रूप में कर सकें।

- पत्र में केजरीवाल ने भागवत के समक्ष सवाल उठाया कि क्या वे भाजपा के चुनाव जीतने के "हथकण्डों" का, जैसे वोटर में पैसा बांटना, वोटर लिस्ट में से प्रतिद्वंदी पार्टी के वोटरों के नाम कटवाने तथा भाजपा समर्थकों के नाम जुड़वाने का समर्थन करते हैं।
- केजरीवाल ने ऐसा ही प्रयास हाल ही में तेलूगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तथा जे.डी.यू के कर्ताधर्ता नीतीश को लिखकर भी किया था।
- केजरीवाल ने दोनों एन.डी.ए. गठबंधन के घटकों को पत्र लिखकर प्रेरित करने का प्रयास किया था कि उन्हें भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिये, भाजपा नेता अमित शाह द्वारा बाबासाहेब अंबेड़कर की प्रतिष्ठा गिराते हुए अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण।
- भाजपा ने प्रत्युत्तर में केजरीवाल पर आरोप लगाया कि आप व उसके नेता केजरीवाल, गैर कानूनी तरीके से रोहिंग्या व बाँग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज व धन देकर दिल्ली में बसने में मदद करते हैं, क्योंकि ये लोग आप के वोट बैंक हैं।

अगर केजरीवाल का उद्देश्य एक राजनैतिक बहस छेड़ना, तथा भाजपा की अनुचित रणनीतियों पर दिल्ली के मतदाताओं के मन में भ्रम और असमंजस पैदा करना है, तो आप नेता सफल होते दिखाई नहीं देते। भागवत को लिखे उनके पत्र पर भाजपा ने तत्काल तथा तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें सलाह दी है कि वे अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये मीडिया का ध्यान खींचने के बजाय, आर.एस.एस. से "सेवा भाव" सीखें। त्रिवेदी ने कहा कि आर.एस.एस. से सम्बद्ध संगठन, "सेवा भारती" गरीब लोगों, जिनमें कच्ची बस्तियों में रहने वाले दलित शामिल हैं, के लिये कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जायेगा

नई दिल्ली, 01 जनवरी। भारत को अमेरिका में बड़ी सफलता मिली है। 26/11 मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के कैनडा कारोबारी तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत लाए जाने की संभावना है। राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी कोर्ट ने अगस्त 2024 में फैसला सुनाते हुए भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने को मंजूरी दी थी।

राणा पर आरोप है कि उसने 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। हेडली ने मुंबई में ठिकानों की रेकी की थी। इससे पहले भारत ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष मजबूत सबूत पेश किए थे, जिनमें राणा की संलिप्तता साफ देखी गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि राणा के खिलाफ भारत में लगे आरोप अमेरिकी अदालतों के मामलों से अलग हैं। दोनों देशों के बीच जो समझौता है उसके तहत राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

- उसके खिलाफ 26/11 के मुंबई हमले के मास्टर माइंड डेविड हेडली की मदद करने के पुख्ता सबूत हैं।

एफ.बी.आई. ने राणा को 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया था। अब उसे भारत लाने की तैयारी जोरों पर है। कोर्ट ने राणा को आतंकवादी संगठन को मदद करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भाजपा ने मेरे क्षेत्र, नई दिल्ली में "ऑपरेशन लोट्स" शुरु किया है'

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 15 दिन में वोटर लिस्ट से 5,000 नाम कटवाने व 7,500 नाम जुड़वाने के आवेदन किए गए हैं

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 1 जनवरी। मीडिया से बात करते हुये, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चुनावों के लिये, भाजपा के पास न तो कोई विज़न है और न उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा, बेईमानीपूर्ण तरीके एवं साधनों को काम में लेते हुये, किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी। जो दाँवपेच उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनाये थे, हम दिल्ली के चुनाव जीतने के लिये, उन्हें काम में नहीं लेने देंगे।" उन्होंने दिल्लीवासियों से कहा कि वे मतदाता सूचियों नाम चैक करते रहें।

आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नई दिल्ली विधान सभा क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व वे (केजरीवाल) करते हैं, में "ऑपरेशन लोटस" शुरू किया है। केजरीवाल ने कहा, "15 दिन में, उन्होंने 5000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं तथा 7500 नये नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये आवेदन किया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता एक लाख छः हजार हैं। फिर चुनाव कराने का मतलब ही क्या है? चुनाव के नाम पर तमाशा हो रहा है।"

- आप नेता एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जो दांवपेंच खेले, उनसे वह दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाएगी।'
- इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेव ने आप पर आरोप लगाया कि वह बाँग्लादेशी घुसपैठियों तथा रोहिंग्या शरणार्थियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रही है।

आप नेता ने कहा कि इससे पहले "समरी रिवीज़न" किया गया था तथा चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी थी। "अगर 12 प्रतिशत अन्तर है, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है, तो क्या चुनाव आयोग का "समरी रिवीज़न" गलत था?"

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा की योजना है कि बाहर से लोग लाये जायें तथा उन्हें दिल्ली के मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाये।

इन आरोपों का खण्डन करते हुये, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेव ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों तथा अगले वर्ष हुये विधान सभा चुनावों के बीच दिल्ली के मतदाताओं की संख्या में बहुत बड़ा उछाल आया था। उन्होंने कहा कि ऐसा ही 2019 के आम चुनावों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मणिपुर संकट कांग्रेस के पुराने पापों की देन है'

माफी मांगने के तुरंत बाद कांग्रेस को कोसा, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जनवरी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा के लिये माफी माँगने के बाद, कांग्रेस पर पलटवार करते हुये, उसे राज्य की समस्याओं के लिये दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि "वर्तमान अशान्ति का कारण पुराने पाप हैं।" उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में न आने का बचाव किया तथा जोर देते हुये कहा कि ये ऐतिहासिक जातीय संघर्ष कांग्रेस नेतृत्व के कारण हुये हैं। उन्होंने पुनर्वास एवं विकास के लिये अपने प्रयासों पर जोर दिया।

2023 में शुरू हुई इस हिंसा के लिए माफी मांगने वाले अपने भाषण में, उन्होंने मणिपुर में ग्रोथ एवं रिकवरी के उपायों का बखान किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के हिंसा-त्रस्त मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर की गई मोदी की आलोचना का जवाब देते हुये, बीरेन सिंह ने मणिपुर की वर्तमान चुनौतियों के लिये "कांग्रेस के पापों" को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने राज्य के संघर्षों के पीछे पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय बताये।

- बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बार भी मणिपुर नहीं आने के कांग्रेस के आरोप के जवाब में कांग्रेस को ही दोषी ठहराया।
- मुख्यमंत्री ने कहा, एक्स पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने यहाँ बर्मा के शरणार्थियों को बसाया तथा म्यांमार के उग्रवादियों से जो समझौता किया उसी का नतीजा है कि प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है।

उन्होंने "एक्स" पर जयराम रमेश को सीधे सम्बोधित करते हुये कहा, "सभी लोग, जिनमें आप भी शामिल हैं, इस बात को जानते हैं कि मणिपुर की वर्तमान अशान्ति कांग्रेस द्वारा अतीत में किये गये पापों का परिणाम है।" उन्होंने बर्मा के शरणार्थियों को बसाने, तथा म्यांमार के उग्रवादियों के साथ "सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स" समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने का हवाला दिया। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि इन दोनों कामों की शुरूआत उस समय हुई थी, जब केन्द्र सरकार में पी. चिदम्बरम गृहमंत्री थे।

अब फ्लाइट में मिलेगा वाई फाई

नई दिल्ली 1 जनवरी। अगली बार आप जब भी एयर इंडिया की फ्लाइट से टेक ऑफ करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसी किसी भी डिवाइस से वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हां, एयर इंडिया ने नए साल एक जनवरी से अपने कुछ एयरक्राफ्ट में वाई-फाई सिस्टम शुरू कर दिया है। फिलहाल यह सर्विस अभी चुनिंदा घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट में फ्री में दी जा रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसका दायरा बढ़ ाते हुए यात्रियों से इसका चार्ज लेना शुरू कर दिया जाएगा।

- एयर इंडिया ने दस हजार फीट की ऊंचाई पर इंटरनैट सुविधा देने के लिए वाई फाई सर्विस शुरू की है।

एयर इंडिया के चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर राजेश डोगरा ने बताया कि सर्विस का फायदा प्लेन के जमीन से 10 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से ही मिलना शुरू होगा। फ्लाइट जब टेक ऑफ और लैंड कर रही होगी, तब वाई-फाई कनेक्ट नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूक्रेन ने यूरोप को रूस से गैस व पेट्रोल की सप्लाई का रास्ता बंद किया

रूस की गैस व पेट्रोल पाइप लाइन यूक्रेन होकर ही पश्चिमी यूरोप पहुँचती थी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जनवरी। रूस से यूरोपियन देशों को प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति करने वाली पाइप लाइन्स को यूक्रेन ने बंद कर दिया है। इन्हें लम्बे समय से पश्चिमी यूरोप के लिए बेहर संवेदनशील माना जा रहा था, क्योंकि कोई भी छोटी सी गड़बड़ी बड़ा विनाश कर सकती थी।

इसने रूस यूक्रेन संघर्ष को और भी हाई पिच पर पहुँचा दिया है। रूस तेल और गैस सैक्टर से ही प्रतिबंधों का दबाव झेल रहा है, जिसकी वजह से रूस अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। रूस से तेल और गैस खरीद पर प्रतिबंध ने रूस के विकल्प सीमित कर दिए हैं।

इन प्रतिबंधों से भी आगे बढ़कर यूक्रेन ने पाइप लाइन बंद कर दी है, जिससे जो चंद यूरोपियन देश रूस से गैस खरीद रहे थे, उन्हें भी आपूर्ति बंद हो गई है। इन कुछ नॉर्थ यूरोपियन देशों ने रूस की गैस पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपना लिए हैं।

- गैस पाइप लाइन बंद करने से रूस की आर्थिक नुकसान (5 अरब डॉलर) तो होगा ही, साथ ही इस बर्फीली सर्दी के मौसम में पश्चिमी यूरोप के देशों में घरों को गर्म करने में जरूरी रूसी गैस की सप्लाई से वंचित रहना पड़ेगा।
- कई पश्चिमी यूरोप के देश, रूस से गैस प्राप्तकरने के लिये वैकल्पिक रास्ता ढूंढ़ने को मजबूर है, जैसे टर्की होकर नई पाइप लाइन बिछाना, पर, नई पाइप लाईन के अपने जोखिम हैं तथा नई पाइप लाइन फटाफट नहीं बिछायी जा सकती।
- सबसे ज्यादा समस्या जर्मनी के सामने है, क्यों, एंजिला मार्केल के चांसलरशिप के समय, जर्मनी ने, अपने लिये गैस के सारे रास्ते बंद करके, केवल रूस से आने वाली गैस पर निर्भर हो गई थी।

जर्मनी एक प्रमुख उदाहरण है, जो एंजेला मर्केल के शासन में ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर था, पर अब उसने अन्य विकल्प अपनाने शुरु कर दिए हैं।

यूक्रेन ने कहा है कि उसने अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र गैस सप्लाई रोक दी है। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। तब से ही पाइप लाइन बंद होने की आशंका थी। इस कदम से रूस की बेचैनी और बढ़ जाएगी। यूक्रेन से गुजरने वाली पाइप लाइन के जरिए रूस एक साल में 5 अरब डॉलर की गैस बेचता है। इसी पाइप लाइन से गैस मध्य व दक्षिणी यूरोप के कई देशों तक पहुँचती है। अब से यूक्रेन ने पाइप लाइन बंद कर दी है तो इन देशों को कड़ाके की ठंड में पावर ब्लैक आउट का सामना करना पड़ सकता है।

प्राकृतिक गैस आपूर्ति में बाधा पड़ने से इसके दाम भी बढ़ जाएंगे, इससे इन देशों में सरकारों के खिलाफ असंतोष भड़केगा।

यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूक्रेन रूट को महत्वपूर्ण लिंक के रूप में देखा जाता था, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। इस पाइप लाइन के भविष्य पर प्रश्नचिंह लगा हुआ था। यूक्रेन पाइप लाइन बंद करने और अपने क्षेत्र से आपूर्ति की अनुमति नहीं देने की धमकी दे रहा था।

रूस की प्राकृतिक तेल एवं गैस कम्पनी गैज़प्रॉम ने रूस से पश्चिमी यूरोप तक गैस भेजने के लिए पाइप लाइन बिछाने का अनुबंध किया था। इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्र ने फसल बीमा का समय व आवंटन बढाया

नई दिल्ली, 01 जनवरी। केंद्र ने बुधवार को दो फसल बीमा योजनाओं -पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस - को वर्ष 2025-26 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग कोष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।

- केन्द्र सरकार ने कहा कि दायरा बढ़ाने से 4 करोड़ और किसान लाभांवित होंगे।

मोदी ने एक्स पर लिखा, नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बजट 2025-26 में कॉरपोरेट टैक्स रिफॉर्म व एफ.डी.आई. (फॉरैन डायरेक्ट इन्वेस्टमैंट पर फोकस रखेंगी वित्त मंत्री

टैक्स रिफॉर्म का अर्थ होगा, स्टार्टअप को टैक्स की रियायतें, कॉरपोरेट टैक्स दरों का सरलीकरण तथा फॉरैन इन्वेस्टमैंट को बढ़ावा देने के लिये रियायतें

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जनवरी। बजट पेश होने के दिन करीब आ रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि देश के आर्थिक विकास को और तेज करने के लिए वित्त मंत्री आर्थिक सुधारों की घोषणा कर सकती हैं। वे आगामी केन्द्रीय बज़ट में महत्वपूर्ण कर सुधारों की घोषणा कर सकती हैं और देश की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए फॉरैन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट (एफ.डी.आई.) को प्रोत्साहन देने के लिए भी कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं।

जो कदम उठाए जाने की संभावना है, उनमें प्रमुख हैं, स्टार्टअप्स को टैक्स में लाभ देना, कॉरपोरेट टैक्स की रेट को तर्क संगत बनाना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एफ.डी.आई. को विशेष प्रोत्साहन देना। व्यवसायिक हित में कदम उठाकर सरकार का लक्ष्य भारत के विकास को गति देना है। विशेष जोर कॉरपोरेट टैक्स सुधार पर और एफ.डी.आई. का प्रवाह बढ़ाने पर दिया जाएगा।

बिज़नैस को आसान बनाने वाले कायदे-कानूनों को प्रोत्साहन दिए जाने की उम्मीद है, खासकर स्टार्टअप्स और छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों के लिए। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा है। सरकार इनको शुरुआत में सहायता देने के लिए लक्षित करों में छूट देगी।

- स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ावा देने के लिये भी टैक्स रिलीफ की घोषणा कर सकती हैं वित्त मंत्री।
- इस प्रकार उभरते सैक्टर, "रिन्युएबल एनर्जी" इलैक्ट्रिक वाहन तथा डिजीटल टैक्नॉलजी, के क्षेत्र में टैक्स रिलीफ दी जायेगी, इस क्षेत्र में पूँजी निवेश बढ़ाने के लिये।
- "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नैस" को मजबूत करने की दृष्टि से टैक्स विवाद निपटाने का रास्ता आसान किया जा सकता है।

संभावित सुधारों में टैक्नॉलजी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे प्राथमिक क्षेत्र के स्टार्टअप को टैक्स में राहत दी जाएगी। नवाचार को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में नए व्यवसायों की कर अवकाश अवधि बढ़ाई जाएगी और छोटे उद्योगों के लिए जी.एस.टी. को सरल बनाया जाएगा।

वर्ष 2019 में कॉरपोरेट टैक्स रेट में भारी कटौती की गई थी और इस बार भी सरकार कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर सकती है या नई टैक्स स्लैब घोषित कर सकती है। इन उपायों से ज्यादा उद्योगों को राहत मिल सकती है। खासकर उनको, जिनके ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, पर वे इन फायदों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं।

उभरते हुए क्षेत्रों जैसे अक्षय ऊर्जा, ई-वाहन और डिजिटल टैक्नॉलजी आदि में भी प्रोत्साहन लागू किए जा सकते है, ताकि इनके लिए एफ.डी.आई. को आकर्षित किया जा सके और इनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई जा सके।

"ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नैस" को बढ़ाने के लिये वित्त मंत्री टैक्स विवादों के त्वरित हल के लिए कुछ कदम उठाने की घोषणा कर सकती है। इस प्रस्ताव में त्वरित समझौते के लिए एक मजबूत, फ्रेमवर्क बनाना, इंसानी हस्तक्षेप को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बराड़ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने

नयी दिल्ली, 01 जनवरी। सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को उसी न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने के निर्णय की बुधवार को घोषणा की। विधि एवं न्याय मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को उसी न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति बराड़ की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।